(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 On-time completion of externally aided projects	0.0	0.0	0.0	0.5
4 Success in Land Reforms	0.0	0.0	0.0	0.5
(v) Special Problems	10.0	10.0	15.0	7.5
TOTAL	10.0	100.0	100.0	100.0

Note Prior to Fourth Five Year Plan (1969-74) allocations varied from scheme to scheme. There was no formula as such for allocation of Central assistance for States' Plan. Thus, schematic pattern was in vogue.

मध्य प्रदेश में स्वीकृत परियोजनाएं

2598. **श्री गोविन्दराम मिरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान सरकार द्वारा कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई तथा उनके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ;

(ख) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी परियोजनाओं को स्वीकृत करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया गया है अथवा किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार परियोजनाओं हेतु आदिवासी भूमि का हस्तांतरण केन्द्रीय सरकार के नाम से करने संबंधी समस्या के निराकरण हेतु विचार कर रही है ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बाघ एवं शेरों में ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु 65 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा था ; और

(ङ) क्या सरकार उसे वर्ष 1997-98 में स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती र नमाला [illegible] मंत्री) : (क) और (ख) मंत्रालय की दृष्टि में योजना आयोग द्वारा प्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले में "बांस के पौधे लगाने और पुनर्वास" पर एक परियोजना प्रस्ताव की 1995-96 में स्वीकृति दी गई थी इस परियोजना की लागत 23.913 मिलियन रु० थी और इसका वित्त पोषण इण्डो-कनाडियन एनवाइरनमेंट फैसिलटी द्वारा किया जाना था।

दिनांक 4-2-1997 को जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिश के अंतर्गत अपर बेड़ा मझली सिंचाई परियोजना को योजना आयोग में प्राप्त किया गया था । राज्य सरकार द्वारा कुछ शर्तों का अनुपालन करने के बाद यह निदेश स्वीकृति के लिए इस परियोजना पर विचार करेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) पर्यटन विभाग ने 1997-98 के दौरान 66 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए ओरछा में सोन्द इट लुमीरी (एसईएल) प्रदर्शन को प्राथमिकता के रूप में रखा गया है। इस परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार से मार्ग निर्देशिकाओं के अनुरूप विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करेगी ।

Maharashtra Government's schemes for inclusion in the Ninth Five Year Plan

2599. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Maharashtra Government has forwarded any projects

schemes for inclusion in the Ninth Five Year Plan;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any decision has been taken with regard thereto; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) to (d) The Government of Maharashtra had proposed a Ninth Plan outlay of Rs. 45125 crores which was agreed to by the Planning Commission. The specific projects/schemes for inclusion within the overall plan ceiling of Rs. 45125 crores in the Ninth Plan are yet to be finalised.

रोजगार सृजित करने का लक्ष्य

2600. **श्री अजीत जोगी :**

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "नई आर्थिक नीति" के अंतर्गत रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं ;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर) : (क) से (घ) नई आर्थिक नीति के पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। फिर भी आठवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई रोजगार कार्यनीति का उद्देश्य मध्यवर्ती परिदृश्य में रोजगार पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है ताकि अगले 10 वर्षों के अन्दर बेरोजगारी को नगण्य स्तर पर लाया जा सके। वर्ष 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोजगार की वृद्धि दर 2.6 से 2.8 प्रतिशत तक वार्षिक प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए रोजगार एवं बेरोजगार से सम्बन्धित पंचवर्षीय सर्वेक्षण देश में रोजगार एवं बेरोजगारी के बारे में व्यापक आंकड़े प्रदान करते हैं। ऐसे अद्यतन सर्वेक्षण 1993-94 की अवधि में संबंधित है (50वां राउण्ड)। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अद्यतन सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के अनुसार 1987-88 और 1993-94 के दौरान देश में रोजगार की वृद्धि 2.23 प्रतिशत वार्षिक हुई है जो 2.6 से 2.8 प्रतिशत के वार्षिक आठवीं योजना लक्ष्य से कम है।

रोजगार की वृद्धि दर की उपलब्धि महत्वपूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर और क्षेत्रकीय उप क्षेत्रकीय वृद्धि पैटर्न पर निर्भर करती है। वर्ष 1987-88 से वर्ष 1993-94 के दौरान पाई गई 2.23 प्रतिशत की रोजगार वृद्धि दर में आठवीं पंचवर्षीय योजना के केवल दो प्रारंभिक वर्ष ही आते हैं जिसके दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत वार्षिक के आठवीं योजना लक्ष्य से कम रही है।

Implementation of MPLADS by NGOs

2601. SHRIMATI BASANTI SARMA :

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have issued instruction No. 3/97,